

कृ,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ७ अगस्त, 2014

विषय:—जनपद चम्पावत में लोहाघाट छमनिया चौड़ पऊ में स्टेडियम निर्माण हेतु 300 नाली (6.00 हैरो) भूमि खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2036/सात—भू0आ0/2013 दि0—1.4. 2013 एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0—7154/रा0प0/2013 दि0—19.12.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद चम्पावत की तहसील लोहाघाट, प0क्षे0 पाटन के ग्राम पऊ के गैर ज0व10 ख0खा0 सं0—640 के खेत सं0—12460 मध्ये 300 नाली (6.00 हैरो) जो श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद भूमि है, को वित्त अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या—260/वित्त अनुभाग—3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के परामर्श/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तान्तरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- 8— प्रश्नगत नॉन जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9— इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०) / (सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ०प०संख्या- १५ / समदिनांकित/ 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
उप सचिव।